

संपादकीय

भारतीय खाने का स्वाद

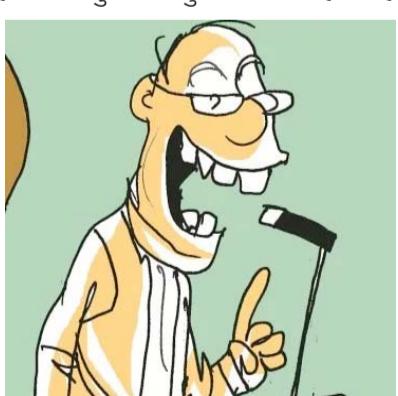
यह मौजूदा वक्त की विडंबना है कि आय बढ़ने के साथ लोगों ने घर में बने खाने की बजाय डिब्बाबंद प्रसंस्कृत खाने को तरजीह देना शुरू कर दिया है। सूचना माध्यमों के जरिये तुरत-फुरत के खाने के विज्ञापनों का इतने आक्रामक ढंग से प्रचार किया जाता है कि बच्चे क्या, बड़े भी डिब्बाबंद खाने के मुरीद होने लगते हैं। यह जानते हुए कि यह उनकी सेहत पर भारी है। जब घर के बड़े-बुजुर्ग इससे बचाव की सलाह देते हैं तो वे इसे पुरातनपंथी सोच करार दे देते हैं। लेकिन डिब्बाबंद खाने की मुहिम चलाने वाले पश्चिमी देशों को भी अब अहसास हो चला है कि डिब्बाबंद खाने से समय से पहले बुढ़ापा दस्तक देने लगता है। खानपान की पश्चिमी संस्कृति के बाहक इटली में हुए एक शोध ने विकसित देशों को भी नींद से जगाया है। दरअसल, इटली के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी के एक हालिया शोध ने फिक्र बढ़ाने वाला निष्कर्ष दिया है कि डिब्बाबंद भोजन के जरूरत से ज्यादा सेवन से व्यक्ति का शरीर समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसके सेवन से हमारे शरीर की कोशिकाएं और ऊतक समय से पहले वृद्ध होने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करता है तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। इस शोध में करीब साढ़े बाइस हजार लोगों को शामिल किया गया। निष्कर्ष में पाया गया कि अधिक मात्रा में जंक फूड व प्रसंस्कृत भोजन का उपभोग करने वाले लोगों की जैविक उप्र अधिक दर्ज की गई। वैज्ञानिकों का दावा है कि हमारे खाने में शामिल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के मुक्त कण अन्य स्वरूप अणुओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया देते हैं। विता की बात यह है कि ये न केवल डीएनए व आरएनए बल्कि प्रोटीन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जिससे समय से पहले ही शरीर की कोशिकाएं मरने लगती हैं। अंततः शरीर समय से पहले बूढ़ा होने लगता है। वहीं आशंका जतायी जा रही है कि रासायनिक पदार्थों द्वारा संरक्षित डिब्बाबंद खाना हमारे शरीर में सूजन भी पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं कालांतर व्यक्ति मोटापा, हृदय रोग, दूसरी श्रेणी के मधुमेह व गठिया जैसे रोगों का भी शिकार हो सकता है। दरअसल, खाद्य पदार्थों का बाजार चलाने वाली कंपनियों की कोशिश होती है कि खाने को देर तक संरक्षित किया जाए। खाद्यान को प्रसंस्कृत करने के लिये सुरक्षित रखने वाले रासायनिक पदार्थों व सोडियम का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अधिक मात्रा में चीनी तथा शरीर के लिये नुकसानदायक रसायन, वसा व कार्बोहाइड्रेट भी खाने को देर तक चलने लायक बनाने के लिये इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आखिरकार हमारी सेहत से खिलवाड़ ही करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कंपनियां अधिक मात्रा में स्टार्च का भी प्रयोग करती हैं। ये कालांतर शरीर में शूगर बढ़ने से मधुमेह का खतरा पैदा कर सकती हैं। अधिक तेल भी सेहत के लिये घातक होता है। सेहत

इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अधिक मात्रा में चीनी तथा शरीर के लिये नुकसानदायक रसायन, वसा व कार्बोहाइड्रेट भी खाने को देर तक चलने लायक बनाने के लिये इस्तेमाल किए जाते हैं जो आखिरकार हमारी सेहत से खिलवाड़ ही करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कंपनियां अधिक मात्रा में स्टार्च का भी प्रयोग करती हैं ऐसे कालांतर शरीर में शूगर बढ़ने से मधुमेह का खतरा पैदा कर सकती हैं। अधिक तेल भी सेहत के लिये घातक होता है। सेहत वैज्ञानिक लंबे अरसे से कहते रहे हैं कि डिब्बाबंद खाना व जंकफूड शरीर में मोटापा बढ़ाता है। दरअसल, इसमें विद्यमान ट्रांस फैट कालांतर शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इससे बाद में कहर के रोग पैदा हो जाते हैं। विशेषकर दिल के रोगों के लिये यह घातक साबित हो सकता है। एक अध्ययन बताता है कि हाल के वर्षों में भारतीयों के खाने में डिब्बाबंद भोजन का हिस्सा बढ़ा है एक भारतीय रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि नई पीढ़ी घरों में खाना बनाने के बजाय डिब्बाबंद खाने को तरजीह दे रही है। जो कालांतर गैर संक्रामक रोगों को ही बढ़ावा देता है। विडंबना यह विनां-बाप के मना करने के बावजूद नई पीढ़ी के किशोर व बच्चों डिब्बाबंद खाने और फारस्ट फूड को अपना मुख्य भोजन बना रहे हैं यहीं वजह है कि बड़ी उम्र में होने वाले लाइफस्टाइल के रोग अब बच्चों व किशोरों में भी होने लगे हैं। निश्चित ही इटली में हुआ शो हमारी आंख खोलने वाला होना चाहिए। लोगों को डिब्बाबंद भोजन से परहेज करने के लिये जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है

ਮੂਲਨਾ ਇੱਸਾਨੀ ਫਿਰਾਤ

मनोज

भूलने लगा हूं। कुछ भी। कैसे भी। हालांकि, अभी यह बीमारी नहीं बनी फिर भी आदत तो बन ही गई है। आदत मेरे लिए परेशानी का सबव कम सरों के लिए ज्यादा हो गई है। कोशिश तो करता हूं, भूली चीज को याद नरे की मगर हो नहीं पाता। एकाध दफा ऐसा भी हुआ है कि दफ्तर को बाकलते वक्त उसका ठिकाना ही भूल गया। लोगों से सही पता पूछना पड़ा। इल्स रखकर भूल जाता हूं। बॉस के साथ मीटिंग का समय भूल जाता। लंच किया या नहीं प्रायः यह तक भूल जाता हूं। दफ्तर से निकलकर जाना भी भूल जाता हूं। सब्जी मंडी में सब्जी वाले को रुपये देना या ना भी भूल जाता हूं। पिछले हफ्ते तो सब्जी से भरा थैला ही कहीं रखकर ल आया। भूलना इंसानी फितरत है। यह न हो तो डॉक्टर्स के कितने लीनिक बंद हो जाएं। इस पर दिया जाने वाला ज्ञान गर्त में चला जाए। बको सब कुछ याद रहना भी ठीक नहीं। इसके अपने खतरे हैं। खतरे या हैं, इस पर आप सोचिए। बीवी को मेरे भूलने की आदत पता है, मगर उसको लेकर हमारे बीच कभी विवाद इसलिए नहीं होता क्योंकि भूलने में मुझसे कहीं अधिक परफेक्ट है। मियां-बीवी के बीच ऐसी समानता लांकि बहुत कम सनने में आती है पर हमारे बीच है। अच्छा ही है नहीं



तो इस मसले पर झागड़े तलाक तक पहुंच जाते। भूलने का जिक्र जब छिड़ता है, उमर शरीफ याद हो आते हैं। साथ याद हो आता है, 'बकरा किस्तों पे' में उनका प्रोफेसर निजामी का किरदार। एक प्रोफेसर जिसे भूलने की बीमारी थी। जो अकसर ही पड़ोसी के घर को अपना घर समझकर घुस जाया करता था। फिर वहाँ से भगाया, दुक्कार जाया करता

था। भूलने की बीमारी पर फेसर की बीवी उससे झगड़ बैठती थी। वही भूलकड़ प्रोफेसर जब संजीदा कर दुनिया—समाज को आईना दिखाता था, तब दिल भर आता था। उस लने का क्या कीजिएगा, जिसे हम जानकर भुलाने में लगे हैं। आपसी रिश्ते ला दिए। मिलना—जुलना भुला दिया। अपने गांव, अपने शहर, अपने इलाके भी भुला दिया। विदेश में बसकर मां—बाप तक को भुला दिया। अब तो लोग न्ताबै पढ़ना भी भुला चुके हैं। सोचता हूँ भूलने की आदत में थोड़ा सुधार करूँ। चीजें याद रखा करूँ। अभी उम्र ही क्या है। इस तरह भूलता रहा तो क दिन कहीं खुद को ही न भूल जाऊँ कि मैं क्या हूँ कौन हूँ? साथ, यह सोचता हूँ अगर मुझ जैसे भूलने वाले दुनिया—समाज में कम हो जाएंगे। बेहतर यादध्याशत वालों का क्या होगा? उनके दिमाग पर तो भयंकर कट आन खड़ा होगा। सबको जब सब याद रहेगा तो समाज—परिवार में गड़े—टंटे कितना हाँगेय कभी विचार कीजिएगा इस पर। इसीलिए मेरा डडा—बहुत भूलकड़ बना रहना ही ठीक है। भूलकड़ हूँ तो सेफ हूँ।

‘आयुष्मान’ पर केंद्र व दिल्ली सरकार में घमासान

योजना को खुद लागू करेंगे। लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। इसके पीछे आप की राजनीतिक जिद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर 6.5 लाख से अधिक पात्र परिवारों और 70 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को केंद्र की आयुष्मान योजना से वंचित कर रही है। इसके विपरीत, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि उनकी सरकार पहले से ही दिल्लीवासियों को मुफ्त इलाज दे रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी प्राथमिकता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान योजना लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे दिल्ली सरकार की मौजूदा योजनाओं को बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों योजनाओं में कुछ विरोधाभास हैं। आयुष्मान योजना में कुछ शर्तें उदाहरण के लिए, यदि का खर्च 10 लाख रुपये पांच लाख रुपये का अभुगतान परिवार को करना। इसके विपरीत, दिल्ली की स्वास्थ्य योजना में कोई सीमा नहीं है। दिल्ली राज्य आयुष्मान योजना के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लागू पर काम कर रही है, ताकि योजनाओं के लाभ एक नागरिकों को मिल सकें और कोई व्यवधान न आये।

आयुष्मान भारत सरकार का लाभ लेने वाले कुछ विशेष मानदंडों की जरूरी है, जबकि दिल्ली की स्वास्थ्य योजना में सभी अस्पतालों में गरीब से अमीर तक, सभी को मुफ्त की सुविधा मिलती है, बिना

और श्रेणियां हैं, जिनके तहत यदि किसी परिवार के पास फ्रिज, दोपहिया वाहन या पक्का मकान हो, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, आयुष्मान योजना में एक परिवार के लिए प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक इलाज की सीमा तय की गई है। यदि एक परिवार में दो लोग बीमार होते हैं, तो अतिरिक्त खर्च उन्हें अपनी जेब से करना पड़ेगा। खर्च सीमा के। अगर सरकार को आयुष्मान लागू करने की वास्तविक होती, तो यह योजना पश्चलागू हो चुकी है दिल्लीवासियों को चाहे वह योजना हो या राज्य की, से लाभ मिल सकता मुख्यमंत्री का यह कहना आयुष्मान योजना लागू चाहते हैं, इसे समझना मु

है, क्योंकि यह लोकहितकारी नीति के खिलाफ लगता है। गौरतलब है कि अक्टूबर, 2024 तक केन्द्र शासित प्रदेश सहित देश के अन्य 36 राज्यों में से 33 में इस योजना को लागू किया जा चुका है। दिल्ली में इस योजना को लागू करने में आप पार्टी ना-नुकर करती रही है। इसके पीछे उसके कुछ तर्क हैं। जिसके परिणामस्वरूप करीब 5 लाख लक्षित लाभार्थी इस स्वास्थ्य कवर से बचित हैं जो उन्हें पंजीकृत सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के विशाल नेटवर्क में देखभाल में

लेए
पूर्ति
कार
नारी
कर
जाज
उसी
ल्ली
नना
छा
ही
ती।
की
ननों
गा।
वे
रना
फल

होने वाले भारी खर्च से बचायेगा। दरअसल, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आयुष्मान योजना के संचालन में 60-40 का अनुपात है। यानी इसमें 60 फीसदी हिस्सा केन्द्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी। दिल्ली में यदि यह योजना लागू होती है तो केन्द्र 47 करोड़ दिल्ली को देता। जबकि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा पहले से ही प्रदान कर रही है। उस दशा में वह आयुष्मान योजना के तहत 40 फीसदी अंशदान कर्यों दे।

यह भी जान लें कि आयुष्मान योजना के तहत कुछ विशिष्ट बीमारियों का इलाज किया जाता

The logo consists of a circular emblem. Inside the circle is a stylized green and orange lotus flower. The text "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" is written in a semi-circle along the top inner edge. At the bottom of the circle, the text "आयुष्मान भारत" is written. Below the circle, the acronym "PM-JAY" is displayed in large, bold, black letters.

है। इसके विपरीत, दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना में किसी भी प्रकार की बीमारी के इलाज पर कोई विशेष बाध्यता नहीं है। सच तो यह है कि आयुष्मान योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोगों यानी बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। भाजपा सांसदों की मानें तो दिल्ली में इस योजना को लागू न करना उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है जबकि दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली वासियों के लिए आयुष्मान योजना किसी भी दृष्टि से लाभदायक नहीं है। बहरहाल, यह मसला दोनों दल के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है। इसे यदि यूं कहें कि यह मुश्ख पूरी तरह राजनीति प्रेरित है। इसका इतना जरूर है कि यदि किसी योजना में जनता का भला होता तो उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। जनता का हित किसी भी तरह, कौन्तों भी हो और वह किसी भी योजना व तहत हो, सरकारों को उसे स्वीकार करना चाहिए। उसमें बाधक बनना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

भाजपा के विलाफ 27 में फिर बदलेगा सियासी समीकरण

अजय

अजय
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से सियासी समीकरण काफी तेजी के साथ बदल रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की विरोध की हांडी नहीं पक पाने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से नए सियासी समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं। इस नये समीकरण में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का अहम रोल हो सकता है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दिये जाने की मांग का भी समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव के समय तक समाजवादी पार्टी कांग्रेसी पंजे से अपना हाथ छुड़ाकर ममता बनर्जी के कहने पर एक बार फिर से मायावती के सात बुआ भतीजे वाला रिश्ता निभाते नजर आए। ऐसा होता है तो यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। यह संभावना है इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों या महीनों से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। सपा—कांग्रेस के बीच दूरिया लगातार बढ़ने के साथ एक—दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी भी हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की नाकामी भी इसमें एक अहम कड़ी समझा जा रहा है। यही दूरियां ही हैं कि संसद के अंदर भी सपा—कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर मजबूती से एक साथ नहीं दिख रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि संभल मामले में उसके सांसद पर मुकदमे दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने उस तरह विरोध नहीं किया जैसी उससे अपेक्षा थी। बताते हैं कि लोकसभा में फैजाबाद (अयोध्या) के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सीट पीछे होने पर भी दोनों दलों के रिश्तों में दरार आई है। सपा का मानना है कि सीटिंग प्लान पर बात के समय कांग्रेस ने उसे भरोसे में नहीं लिया। वहीं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सदन में अदाणी मामले में उसे सपा का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। हाल यह है कि जेल में बंद सपा के कदावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने भी इंडिया ब्लॉक को जेल से एक संदेश भेजा है। इसमें उन्होंने कि इंडिया ब्लॉक को मुस्लिमों पर हो रहे हमलों पर अपनी स्पष्ट करनी चाहिए। सपा उन्होंने समाजवादी पार्टी लिखा कि संभल की घट जैसे ही रामपुर में हुए अपराधों का मुद्दा भी संसद में उत्तर मजबूती से उठाना चाहिए। और सपा के बीच दूरियां तब बढ़ गईं जब सपा कि तब कहा जाने लगा कि इंडिया चुनाव का नेतृत्व कांग्रेस की तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो बनर्जी को दिए जाने पर समर्थन नहीं है। बता दें लोक सपा चुनाव के बाद कई चुनाव कांग्रेस की लगातार हार रही है। इंडिया गठबंधन में अंतर्विरोध रहे हैं। उधर दूसरी तरफ यह भी है कि यूपी की राजनीति एक बार फिर पलट सकती है। सपा और कांग्रेस के बीच दूरियों के बीच मायावती वाली नई राजनीतिक समीकरण जन्म दे सकता है। बहरात नेताओं का कहना है कि मामले में उसके सांसद पर दर्ज किए जाने का कांग्रेस

भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक को मुसलमानों पर हो रहे हमलों पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी लिखा कि संभल की घटना के जैसे ही रामपुर में हुए अत्याचार का मुद्दा भी संसद में उतनी ही मजबूती से उठाना चाहिए। कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां तब और बढ़ गईं जब सपा कि तरफ से कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जगह तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को दिए जाने पर सपा को एतराज नहीं है। बता दें लोकसभा चुनाव के बाद कई चुनावों में कांग्रेस की लगातार हार के बाद इंडिया गठबंधन में अंतर्विरोध बढ़ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि यूपी की राजनीति एक बार फिर पलट सकती है। सपा और कांग्रेस के बीच आई दूरियों के बीच मायावती का रुख नई राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकता है। बहराल, सपा नेताओं का कहना है कि संभल मामले में उसके सांसद पर मुकदमे दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने उस

बनजो करे। भाजपा को मात देने के लिए रणनीति के साथ जनता के बीच लगातार जुटे रहने की जरूरत है। बात बीएसपी की की जाए तो हरियाणा व महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस व सपा के बीच बढ़ी दूरियों का सियासी लाभ बसपा को मिलने की उम्मीद है। पार्टी तेजी से बदले राजनीतिक घटना पर नजर बनाए हुए है। यदि कांग्रेस और सपा के बीच बात नहीं बनी तो इसकी वजह से बनने वाले तीसरे मोर्चा का बसपा अंग बन सकती है। जानकारों की मानें तो वर्तमान में पार्टी को अपना वजूद बचाने और देश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए इसकी जरूरत भी है। बसपा के इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत मिला था। इससे पहले बसपा दूसरे दलों की मदद से सरकार बनाती रही, जिसका लाभ उसे लोकसभा चुनावों में भी मिलता गया। वर्ष 2012 में बसपा ने फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जो गलत साबित हुआ। यही हाल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। 2019 में बसपा ने सपा व साथ गठजोड़ कर लोकसभा चुनाव लड़ा और 10 संसदों वाली पाठ बनी। हालांकि इसके बाद वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव और 2021 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़े से उसे भारी नुकसान का सामने करना पड़ गया। अब पार्टी का उम्मीदें तीसरा मोर्चा बनने पर टिक रहे। वैसे तो मायावती सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है लेकिन पश्चिम बंगाल व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों दलों को एक मंच पर ला सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो कांग्रेस को दरकिनार कर अगली तीसरा मोर्चा बना तो ममता बनर्जी उसकी निर्विवाद नेता बन सकती है। पहले उन्हें मायावती से चुनौती मिलने के जो समीकरण बने थे, वे बीते चुनावों में बसपा के लगातार घटते जनाधार की वजह से ध्वस्त हो चुके हैं। अब बसपा को अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने वाले दूसरे दलों का सहारा लेना पसंद सकता है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने पुराने बसपाइयों को भी वापस आने का बुलावा दिया है।

‘कमजोर होता मजबूती देने वाला’ ‘फौलादी ढंचा’

संजय

संजय
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे द्वारा खुद को गृह
विभाग सौंपे जाने की मांग करने पर
हैरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी
तरह, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं
कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यह

नॉर्थ ब्लॉक के पूरबी विंग (गृह मंत्रालय)
को छोड़कर पुनः पश्चिमी विंग (वित्त
मंत्रालय) में जाने की इच्छा जताई।
मैंने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों
करना चाहते हैं। आखिरकार, सरदार
पटेल के दिनों से ही गृह विभाग को
दूसरा सबसे अहम मंत्रालय माना

सलाहकार पद की सृजना होने के बाद, अधिकांश खुफिया एजेंसियों के प्रमुख सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर, वित्त मंत्री के अधीन कुछ खुफिया एजेंसियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण

पद— कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की कुर्सी पर अभी भी उनका वर्चस्व है (हालांकि, पीएन हक्सर और ब्रजेश मिश्रा नियम के अपवाद थे) —लेकिन राज्यों की राजधानियों में उनका रोब—दाब प्रमुख पुलिस से नीचे है। अपने तौर पर, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) ने न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय पाया है बल्कि कई जांच एजेंसियों पर अपना नियंत्रण भी बढ़ाया है। साथ ही नौकरशाही प्रणाली के भीतर काफी शक्ति प्राप्त कर ली है। नौकरशाह ढांचे में, राज्य और केंद्रीय स्तर पर, आईएएस अधिकारियों की तुलना में आईपीएस अधिकारी कहीं अधिक शक्तिशाली बन गए हैं। आईएएस की तुलना में आईपीएस अधिकारी अटिक संख्या में राज्यपाल बने हैं। नई दिल्ली के सत्ता तंत्र में, यह सुनिश्चित करते हुए कि अन्य मंत्रालयों के तहत आती जांच एजेंसियों के प्रमुख भी केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने हाथ में काफी शक्ति समेट ली है। राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर, सिविल सेवाओं के अन्य सदस्यों की सापेक्षता में पुलिस ने काफी शक्ति पा ली है। यह 'उपलब्धि' उन्होंने राजनीतिक आकाओं के मनमाफिक औजार बनकर हासिल की है। चार दशक पहले की एक सच्ची कहानी बताता हूँ। उस समय मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक संकाय में कार्यरत था। मेरा एक छात्र अपनी मास्टर डिप्री पूरी करने के बाद डॉक्टरेट करना चाहता था। जबकि मुख्यमंत्री

सचिवालय में गैर—आईएएस सचिव के पद पर तैनात उसके पिता चाहते थे कि बेटा सिविल सेवा परीक्षा दे और आईएएस अधिकारी बने। लेकिन पुत्र अपनी पसंद पर अड़ा हुआ था। इसलिए, पिता ने अपने बॉस और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चेन्ना रेण्णी, जो कि तेलंगाना के एक दिग्गज और शक्तिशाली राजनेता थे, उनसे अनुरोध किया कि वे बेटे को 'समझाएं।' रेण्णी ने लड़के को बुलाया और उसके मन की सुनी। उन्होंने पिता से कहा कि वे उन्हें अकेला छोड़ दें। युवक को अपने कमरे में बैठाकर, उन्होंने अपने प्रमुख सचिव, एक आईएएस अधिकारी, को बुलाया। अधिकारी अंदर आया, बैठा, मुख्यमंत्री की कहीं बातें नोट की और बाहर चला गया। फिर रेण्णी ने अपने सुरक्षा प्रमुख, एक आईपीएस अधिकारी, को बुला भेजा। वर्दीधारी वह अधिकारी अंदर आया, उसने मुख्यमंत्री को चुस्त सलामी दी और खड़ा रहा। रेण्णी ने उसे किसी चूक के बारे में डांटा। अधिकारी, जो अभी भी खड़ा था, उसने माफी मांगी, फिर से सलामी दी और जाने की अनुमति मांगी। रेण्णी फिर उस युवक की ओर मुड़े और कहा रु 'कल, तुम्हारे एक प्रोफेसर मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने नाना आरोपों से भरा एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुझे इस बारे में खबू सुनाया कि मेरी सरकार कितनी अयोग्य और भ्रष्ट है। मुझे उन्हें सुनना पड़ा। बल्कि, मैंने उन्हें एक कप चाय भी पिलाई। सो, आज, तुमने देखा कि अधिकारियों

और मुख्यमंत्री के बीच व्यवहार कैसे रहता है। अगर तुम पीएचडी करोगे और एक प्रोफेसर बनोगे और किसी मुख्यमंत्री से मिलने जाओगे, तो तुम्हारा साथ उचित सम्मान से पेश आया जाएगा। अगर तुम आईएएस बनोगे तो तुम्हें संभालने के लिए दिलचस्पी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यदि एक पुलिस अधिकारी बन गए, तो मैं जैसे राजनेताओं को सलाम ठोकना पड़ेगी। अब यह तुम तय करो विनियोग कीसी जिंदगी चाहिए।' लड़का दंड रह गया, जबकि उसके पिता मुख्यमंत्री के दिए इस छोटे से सबक से असंतुष्ट थे। वह युवक बाद में अमेरिका चल गया। जब मैंने यह किस्सा उसका मुंह से सुना, तो रेण्णी के लिए मेरा सम्मान एकाएक बढ़ गया। अपनी पीढ़ी की तरह वे भी अलग किस्म वाले राजनेता थे। आज की तरह वे लोनिर्लज्ज होकर सत्ता का इस्तेमाल नहीं करते थे। तीस साल पहले एनएन वोहरा, एक प्रतिष्ठित सिविल नौकरशाह, जिन्होंने केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव और जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल जैसे प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहराव द्वारा बनाई समिति के तहत एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट 'पुलिस राजनेता, अपराध सिंडिकेट और माफिया के बीच सांठ-गांठ' की जांच पर आधारित थी। वर्ष 1993 की इस बेहद संवेदनशील रिपोर्ट का सारांश तो सार्वजनिक किया गया।



जाता रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी गृह मंत्रालय खुद को और वित्त मंत्री का कार्य यशवंत सिंहा जैसे कनिष्ठ नेता को आवंटित करने को कहा। चिदम्बरम का जवाब तीखा और त्वरित था रु किसी संकट की स्थिति के अलावा गृह मंत्रालय में करने-धरने को कुछ विशेष नहीं होता। जबकि वित्त मंत्री का काम चौबीसों घंटे चलता है। मैं अभी भी युवा हूं। मुझे किसी प्रकार के सुरक्ष महकमे की जरूरत नहीं है।' लेकिन जो चिदम्बरम ने नहीं बताया, वह यह है कि गृह मंत्री की असली शक्ति प्रमुख जांच एजेंसियों पर नियंत्रण में निहित है। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा

प्रवर्तन निदेशालय है। आज, कई एजेंसियां, जिनमें बाहरी भौतिक निपटने वाली एजेंसियां भी शामिल हैं, जिसमें समय-समय पर केंद्रीय गृह विप्रोट करती हैं, जिससे राष्ट्रीय शक्तिशाली हो गया है। राजपर, गृह मंत्रालय का नियंत्रण कानून-व्यवस्था का प्रबंधन करता है। खुफिया जानकारी हासिल करनी सीमित नहीं है। सभी सिविल सेवा में पुलिस सबसे शक्तिशाली है। गई है। भले ही केंद्र सरकार अपने महकमों में नियुक्त आईएएस आरपीसी का सामाजिक रूतबा अधिकार जाता है, आर्थिक मंत्रालयों यक्षिता करने वालों के अलावा

